

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

R-3358-II/12

निगरानी क्र०

श्री. पद्मेश च. शिवपुरी

द्वारा आज दि. 1-10-12 को

प्रेरित किया गया है।

कलकत्ता ऑफ कोर्ट

1-10-12

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री. पद्मेश च. शिवपुरी

सिपाई पुत्र जयसिंह आयु 50 वर्ष  
निवासी - फुलीपुरा तहसील- पोहरी  
जिला- शिवपुरी म०प्र०

विरुद्ध

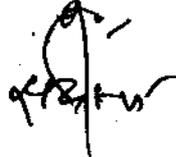
1. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व सचिव  
वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०
2. उपखण्डीय पदाधिकारी महोदय  
पोहरी जिला- शिवपुरी म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.08.12 प्रकरण क्र० 21/11-12 682  
माननीय महोदय प्रार्थी की निगरानी निम्न है ।

1. प्रार्थी ग्राम फुलीपुरा तहसील पोहरी जिला- शिवपुरी का निवासी है और उसके पास में कोई रहने के लिए मकान नहीं है इसलिए उसने जैसा कि पटवारी की रिपोर्ट से प्रतीत होता है सरकारी भूमि पर मकान बना लिया है इस पर से पटवारी ने तहसीलदार को अतिक्रमण की रिपोर्ट की उस पर से तहसीलदार ने 31,750/- रुपये जुर्माना कर दिया जिस को प्रार्थी अपनी गरीबी के कारण अदा नहीं कर पाया उस पर से तहसीलदार महोदय ने माननीय उपखण्डीय पदाधिकारी पोहरी जिला- शिवपुरी ने धारा 248(2) राजस्व संहिता के अंतर्गत रिपोर्ट की ओर उस पर प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हो सका । उसके पश्चात उसने अपने अभिभाषक को जबाब देने के लिए अधिकृत किया ।
  2. इस पर से माननीय उपखण्डीय पदाधिकारी ने एक नोटिस दिया कि क्यों न उसको दीवानी जेल में भेज दिया जाये उस पर से उसके अधिवक्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया और उसमें कहा गया कि वह जेल नहीं भेजा जावे क्योंकि भूमि का पट्टा नये कानून म०प्र० ग्रामों में कि दखलरहित भूमि (विशेष उपबंद) जो म०प्र० राजपत्र में एक्ट नं० 26 सन 1970 में दिनांक 24.10.1970 को प्रकाशित हुआ और उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है और उसके पास मकान नहीं है जो उसी ग्राम में कृषि कार्य से जुड़े हुआ है उसके पक्ष में पट्टा होना चाहिए था नकल कानून प्रस्तुत है ।
  3. माननीय सरपंच महोदय ने भी एक प्रमाण-पत्र दिया कि उसके पास खुद का मकान नहीं है इसलिए उसे रहने का बड़ा संकट है प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।
  4. यह कि, और उसने तमाम उच्च न्यायालय और माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयों का हवाला दिया गया जिसमें यह निर्णीत किया गया कि पटवारी का प्रतिवेदन साक्ष्य नहीं है ।
- माननीय उच्च न्यायालय ने भी महेन्द्र कुमार विरुद्ध म०प्र० राज्य जो म०प्र० रेवेन्यू निर्णय 1993 पृष्ठ 253 में निर्णीत किया गया है कि कथित आक्रमणकारी को साक्ष्य प्रस्तुत किया

1/10/12

W.S. 6

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>25-7-16</p>	<p>आवेदन अति.प्र. प्रकीर्ण के अन्तर्गत अनुपस्थित। आवेदन की ओर से मारुती फॉर्म नहीं है अर्थात् उपरोक्त प्रकार के आवेदन के अनेक वर्ष अग्रिम जागी गई परन्तु कोई ड्यु. नहीं। अतः प्रकीर्ण अर्थात् प्रकीर्ण के द्वारा प्रमाणित हो प्रकीर्ण रिकॉर्ड नहीं है।</p>	<p></p>

M